श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य का जो विचार है वह वर्क्स ऐंड हाउसिंग मिनिस्ट्री से संबंधित है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be parsed." *The* motion *was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Smt. Ram Dulari Sinha regarding consideration of the Punjab Municipal (New Delhi Amendment) Bill, 1984 to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion *was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 15 *were* added to the *Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question *was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Mallikarjun regarding the Delhi Development (Amendment) Bill, 1984 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend J the Delhi Development Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion *was adopted.* MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 11 *were added to the Bill.*

Clause 1, the *Enacting* Formula and the *Title were added to the Bill.*

SHRI MALLIKARJUN. Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 10 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI MALLIKARJUN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question urns put *and the motion was adopted.*

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF 'INDUSTRY— (Contd.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN. Now further discussion on the working of the Ministry of Industry raised by Shri Hukmdeo Narayan Yadav. Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav will continue—not there. Shri Sukomal Sen—not there; Dr. Bapu Kaldate or Shri S. C. Mohunta—not there; Shri Ashwani Kumar—not there; Shri Kalyan Roy—not there. Shri Rama-nand Yadav.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : मान्यवर, मैं उद्योग विभाग के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा)**, पीठासीन हुईं।]

महोदया, उद्योग विभाग बड़े ही कुशल मंत्री जी के हाथों में है जिनका प्रशासन का अनुभव बहुत पुराना है और विचार भी ऐसा है कि समान रूप से सारे देश के विषय में व चिन्तन करते हैं। एक बात इनमें यह भी है कि जो पिछड़े हुये लोग हैं और पिछड़े इलाके हैं उनकी ये बहुत मदद करते हैं।

महोदया, नेहरू जी ने जब इंडस्ट्रियल पालिसी की नींव डाली थी तो उनके सामने एक बहुत बड़ा कांसेप्ट था। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री के सम्बन्ध में उनके मन में बहुत बड़ा कांसेप्ट था क्योंकि वह एक समाजवादी वातावरण में पैदा हुये थे। उनका विचार था कि सोशलिस्ट इंडिया बनाया जाए और जल्दी से जल्दी पश्चिमी देशों के समकक्ष अपने देश को किसी न किसी तरह से इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, अर्थात् पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों के रोल को विजुअलाइज किया था कि वे दोनों साइड बाई साइड अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्रधानता दी थी और उसके आधार पर उन्होंने इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की नींव डाली थी। मान्यवर, उन दिनों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अधिक से अधिक खोलने की बात थी और वे खोली गईं और कुछ इंडस्ट्रीज को तो केवल सरकार ही खोल सकती थी। उसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। उसी के अनुसार नेहरू जी के टाइम में इंडस्ट्रियल रेजलूशन पास हुआ पार्लियामट द्वारा और उसमें इंडस्ट्री को दो भागों में विभक्त किया गया। शेड्यूल बन में उन इंडस्ट्रीज को रखा जो केवल सरकार ही खोल सकती है और बाकी कुछ आइटम्स जो इंडस्ट्रीज के थे उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिये। वैसे आपका जितना लड़ाई का सामान बनने वाला था, हथियार बनने वाले थे, उस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री को एलाऊ नहीं किया। उसमें उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया। महोदया, यह भी सोचा गया था कि 49 और 51 की रेशों रखकर सामूहिक रूप से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंडस्ट्री चलायें, इसका भी एक्सपेरीमेंट किया गया। मान्यवर, यह भी सोचा गया था कि कोई भी डवलपमेंट हो, इंडस्ट्री देश में फैले वह ठीक ढंग से, प्लांड तरीके से हो। किस ऐरिया में इस इंडस्ट्री को होना चाहिये, कितने पैसे की लागत की होनी चाहिये, इन सारी चीजों पर विचार हुआ था। फिर यह सोचा गया था कि जो एरिया काफी अनडेवलप्ड हैं उन एरिया को भी डेवलप्ड किया जाये। यह सब बातें सोच समझ कर नेहरू जी के जमाने में इंडस्ट्रियल पालिसी तय हुई। कुछ दिनों तक यह पालिसी चली और काफी सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ, उसकी काफी प्रगति हुई। काफी पैसा भी लगा। लेकिन बाद में सरकार का भी ध्यान इस क्षेत्र से इस सेक्टर से घटना शुरू हुआ। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थिति जो है उसमें बाद में आऊंगा। जो बैकवर्ड एरियाज के डवलपमेंट की बात है इस पर अपने थोड़े से विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार का उत्तरी हिस्सा, पूर्वांचल का असम, मिजोरम, नागालैंड, ये जो स्टेट्स हैं और बहुत से हिल्ली एरियाज जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आते हैं, पूर्वी हिस्से में आते हैं, बिहार के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सेमें आते हैं वे काफी अनडवलप्ड हैं। ऐसी सूरत म इन एरियाज में डवलपमेंट की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस जो पिछले वर्षों में इशू हुए उसमें महाराष्ट्र को 171 लाइसेंस मिले, पंजाब को 169 लाइसेंस मिले, गुजरात को 115 लाइसेंस मिले। उसी तरह वेस्ट बंगाल को 171 लाइसेंस मिले जबकि 82 में 27 ही मिले थे। आन्ध्र को 63 मिले जबकि 82 में उसे 26 मिले। एरियावाइज

[श्री रामानन्द यादव]

देखा जाए तो जो अधिक विकसित हैं उनको अधिक लाइसेंस मिले। मध्य प्रदेश जो विकसित नहीं है उसको कम मिले। उत्तर प्रदेश जो अधिक विकसित नहीं हैं उसको भी कम मिले। जो गढ़वाल का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूर्वी इलाका उत्तर प्रदेश का हैं, वहां सूखा पड़ता हैं, वहां लोग भूखे मरते हैं, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा हैं वहां पर हर साल बाढ़ आती हैं, कोई इंडस्ट्री वहां नहीं हैं। इक्का दुक्का शुगर का कारखाना हैं। अभी भी एक वर्ग मील में पांच हजार आदमी रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वहां गुरबत हैं। उस इलाके में कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकी हैं। उन इलाकों को इंडस्ट्री खोलने के लाइसेंस नहीं दिये गये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन पर सरकार का जरूर ख्याल रहना चाहिए। क्योंकि शरीर के सारे अंग विकसित नहीं होंगे, एक ही अंग को विकसित कर देंगे तो शरीर स्वस्थ रूप से काम नहीं कर सकेगा। यह भी कहा गया था कि स्माल स्केल इंडस्ट्री को भी काफी प्रश्रय दिया जायेगा क्योंकि इस स्माल स्केल इंडस्ट्री में काफी लोगों को खपत हो सकती थी। यह भी कहा गया था कि घरेलू उद्योग धंधों को भी प्रश्रय दिया जायेगा। इंडस्ट्रीयल पालिसी के अंदर यह भी सोचा गया था।

हमारे घरेलू उद्योग—धन्धों के विषय में श्री लुकमदेव नारायण यादव जी ने काफी चर्चा की हैं। हमारे देश में जितने भी घरेलू उद्योग—धंधे थे वे काफी हद तक खत्म होते जा रहे हैं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस दिशा में जिस गति से प्रगति होना चाहिए थी उतनी गति से प्रगति नहीं हुई हैं। इसका कारण मुझे लगता हैं कि मंत्री जी के और डिपार्टमेंट के प्रयास करने के बावजूद जो लोग स्माल स्केल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उनकी स्वार्थपरता और उनकी निष्क्रियता के कारण इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हुई हैं। वे लोग बहुत जल्दी धनी होना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण स्माल स्केल इंडस्ट्री इस देश में बहुत प्रगति नहीं कर पाई हैं। फिर भी स्माल स्केल इंडस्ट्री ने काफी प्रगति की हैं। आज जरूरत इस बात की हैं कि कुछ ऐसे ग्राइटम्स इसमें रखने की जरूरत हैं जिनको अभी तक आप नहीं रख पाये हैं। आज स्थिति यह हैं कि जो बड़े बड़े मल्टी नेशनल्स हैं उनको छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए भी लायसेंस दिये गये हैं। उनको ये चीजें बनाने के लिए एलाऊ नहीं करना चाहिए। जैसे सिलाई बनाने के लिए उनको लायसेंस दिये गये हैं। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जहां पर आपने इन मल्टी नेशनल्स को छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए भी एलाऊ कर दिया है इनको आप रोकिए और इनकी व्यवस्था कीजिए कि ये चीजें स्माल स्केल सैक्टर में जायें। आप जानते हैं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री इस देश में करीब 35 हजार करोड़ रुपये की आमदनी करती है और इसमें करीब 29 लाख लोग काम करते हैं। अभी स्थिति यह है कि इसमें और भी अधिक लोगों को काम करने की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि काफी इंडस्ट्रीज जो स्माल स्केल सैक्टर में हैं उनको सिक घोषित कर दिया गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक कमेटी का निर्माण करें जो इस बात की जांच करे कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में इतने बड़े पैमाने पर सिकनेस क्यों हो गयी हैं? आजकल यह बात आम हो गई है कि इंडस्ट्री तो खोल दी जाती हैं और लोग सोचते हैं कि सरकार से पैसा मिल

जायगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल जायेगा, बैंकों से पैसा मिल जायेगा, इसलिये इंडस्ट्री को सिक घोषित करने में फायदा है। जब उनको पैसा मिलता है तो वे उस पैसे को दूसरी जगह डायवर्ट कर देते हैं। यही कारण है कि आज अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को सिक घोषित कर दिया जाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार का स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर अधिक से अधिक नियंत्रण होना चाहिये। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि करीब 30 हजार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को इस देश में सिक घोषित कर दिया गया है। इन उद्योगों को फिर से स्वस्थ बनाने के लिये आपको कुछ करना पड़ेगा।

माननीय, बिग इंडस्ट्रीज भी इस देश में काफी बढ़ रही हैं। आपने एम० आर० टी० पी० एक्ट में एमेंडमेंट किया। इसके माध्यम से आपने इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान कर दी कि वे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्दर जो प्रोविजन थे उनमें आपने काफी ढील दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े पूंजीपतियों को यह ढील दिये जाने से क्या कोई फायदा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस एमेंडमेंट के पीछे यह सोचा था कि एम० आर० टी० पी० एक्ट में अमेंडमेंट करके आप इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं जिससे फारेन एक्सचेंज कमाया जा सके और देश में उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें आपको सफलता मिली है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें सफलता नहीं मिली है। बड़े बड़े पूंजीपति इस छूट का फायदा उठा रहे हैं और पहले जो कंट्रोल था उसमें ढील होने के कारण वे मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। आपका काफी पैसा इनकम टैक्स का बकाया पड़ा हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इस ढंग से नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े जो हाउसेज हैं, हिन्दुस्तान के, उन्हीं के डिक्टेशन पर यह होता है, सारी इंडस्ट्रीज चलती है। वह जिस तरह से चाहते हैं सरकार से काम करा लेते हैं। आपने जितने कानून बनाये हैं वे उनका उल्लंघन करते हैं। फिर भी आप उन पर ठीक प्रकार से नियन्त्रण नहीं कर पाते। इस बात की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आपने उनको डिफरेंट कंसेशंस दिये। लेकिन इससे क्या हुआ? बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो कि मोनोपोली ढंग से काफी लाइसेंस ले लेते हैं और एक ही इंडस्ट्री के लाइसेंस कई जगह ले लेते हैं और लाइसेंस एक्वायर करके रख लेते हैं। उसके लिये जो टाइम लाग देते हैं उसके अंदर खोलते नहीं हैं। ऐसे लोग जिनके पास काफी मात्रा में लाइसेंस हैं, इसके लिये एक विदिन बोस कमेटी बनी थी, इसको देखने के लिये, उसका क्या रिजल्ट निकला? यह आपको देखना चाहिये कि ऐसे लोग जो लाइसेंस लेकर बैठे हुये हैं और कारखाने खोलने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उस अवधि, निर्धारित अवधि के अन्दर कारखाना नहीं खोलते हैं उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय महोदया, अब मैं अपने स्टेट के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। महोदया, बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनी। बरौनी में यह रिफाइनरी पब्लिक सैक्टर में बनी और सरकार ने एक कमेटी बनाई इस बात का जांच करने के लिये कि क्या वहां पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। महोदया, उस कमेटी ने निर्णय दिया कि वहां पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है और मैं क्या नहीं सकता कि क्यों सरकार ने बरौनी को छोड़कर इस कम्प्लेक्स के लिये बड़ौदा को चुन लिया और बड़ौदा में पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स बना गया। फिर पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स की बात आई। सरकार

[श्री रामानन्द यादव]

ने एक कमेटी बनाई, उसने भी निर्णय दिया कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में बरौनी में यह कम्पलेक्स बने, लेकिन उसको बरौनी में न खोल करके कुवालो कोई जगह है वहां खोल दिया। महोदया, सेकंड टाइम भी कमेटी बनी थी 1976 में, उसने बरौनी के लिये कहा और सरकार ने ईस्टर्न इंडिया को फैसिलिटीज देने के लिये और कारखाना खोलने के लिये रेकमेंड किया और बरौनी को इसके लिये सूटेबल जगह समझा। वहां की सरकार ने प्रोमिस किया कि हम जमीन दे देंगे और सारी फेसिलिटीज देंगे। लेकिन सरकार ने आज तक वहां काम नहीं किया। वह काम भी नहीं हुआ और वह भी शायद दूसरी जगह चला गया। (**समय की घंटी**) महोदया, . . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : आपने घंटी नहीं सुनी ?

श्री रामानन्द यादव : पांच मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : पांच मिनट नहीं आप एक मिनट में खत्म कीजिये। दूसरे मेम्बर भी अपनी-अपनी स्टेट के बारे में बोलना चाहेंगे।

श्री रामानन्द यादव : वहां से तेष्था कानपुर और गोरखपुर जा रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है कि वह कानपुर और गोरखपुर क्यों जा रहा है जब कि वहां पर, बिहार में यह कारखाना लगाया जा सकता था। कानपुर की रिफाइनरी बाद में बनी। तो महोदया, मैं सरकार से चाहूंगा कि वह पट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स जो बरौनी में बनना है उसको जल्दी से जल्दी इजाजत दी जाये और इस बारे में पुनर्विचार करे कि वहां पर कोल बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाये। कोल बेस्ट इंडस्ट्री स्टेट में एक थी वह भी फर्टिलाइजर की सिन्द्री में, उसको स्कैप कर दिया। अब कोल बैस्ड इंडस्ट्री को उस एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिये जैसे कि हार्ड कोक बनाने के लिये और फर्टिलाइजर के लिये फिर सरकार ने निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। महोदया, 40 प्रतिशत कोयला बिहार में बचा होता है, उसका काफी वैस्ट होता है। उस वैस्ट कोल से वेस्टइंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, आयल बनाया जा सकता है, हाइ पावर डीजल में मिलाकर जिसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में हो सकता है। मेथानोल भी बनाया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : बिहार के दूसरे स्पीकर्ज हैं वे भी बिहार के बारे में बोलेंगे।

श्री रामानन्द यादव : महोदया, बागास बेस्टपेपर फैक्ट्री बनाने की बात बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के उत्तरी जिलों में थी। एक जापानी टीम भी आई उसने अन्वेषण भी किया छानबीन की और फैसला किया कि बेतिया बिहार का एक ऐसा जिला है जहां बागास बेस्ड फैक्टरी खड़ी की जा सकती है लेकिन न मालूम क्यों उसको छोड़ दिया गया है। इस प्रोजेक्ट्स से 250 टन पेपर पैदा हो सकता है। (**समय की घंटी**) महोदया, हमने इस सदन में बार-बार सरकार से प्रार्थना की है कि भविष्य में जो एटोमिक प्लांट बनने वाला है वह बिहार के जादूगुड़ा स्थान पर होना चाहिये क्योंकि वहां पर यूरेनियम जो इस प्लांट के लिये आवश्यक है वह सिंहभूम जिले में काफी मात्रा में पाया जाता है। इसलिये एटोमिक पावर प्लांट वहीं पर बैठाना चाहिये। (**समय की घंटी**) हमारे यहां लोहा बहुत मिलता है और लोहा बेस्ड कारखाना भी स्टील का खोलें जिसके लिये अभी दूसरा कारखाना खोलने वाले हैं तो मनोहरपुर में स्टील का कारखाना खुलना चाहिये ताकि बिहार के लोगों को यह इंडस्ट्री मिल सके और हमारा पिग आइरन. . . (**समय की घंटी**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : यादव जी, प्लीज अब बैठ जाइये।

श्री रामानन्द यादव : महोदया, रोलिंग मिल्ज का और सिनो स्टील प्लांट का मामला पड़ा हुआ है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि कम से कम रोलिंग मिल का और सिनो स्टील प्लांट का जो इंटेंट पड़ा हुआ है आप उसको दे दें ताकि लोग अपना काम कर सकें। हमारे यहां जूट मिल भी कायम हो सकती है (समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) यादव जी अब आपको बैठना पड़ेगा।

श्री रामानन्द यादव : इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा और यह कहना चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष ध्यान दीजिये क्योंकि एक ही स्टेट के कुछ हिस्से है जो डेवलप्ड हैं और कुछ हिस्से हैं जो अनडेवलप्ड हैं जो हिस्से अनडेवलप्ड हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दीजिये। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, पश्चिम हिस्से और बिहार के उत्तरी हिस्से काफी अनडेवलप्ड हैं जहां पर आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग कायम हों। वहां आबादी भी सबसे अधिक है। वहां भुखमरी भी होती है। काफी लोग भूखे मरते हैं। हर साल बाढ़ आती है; बाढ़ से पीड़ित होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदया, सरकार की कुशल नीति के चलते आज भारत ने काफी औद्योगिक क्षमता प्राप्त कर ली है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व के भारत की कोटि-कोटि सर्वहारा दल को रोजी रोटी मिली है और रोजगार मिल रहा है मिलने जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदया ने घोषणा की है अब हिन्दुस्तान में कोई व्यक्ति बे-रोजगार नहीं रहेगा और प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को अवश्य रोजगार दिया जायेगा। मैं उद्योग मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कुशलता अपनी कर्मठता से हिन्दुस्तान के जिले में जाकर के प्रखण्ड और ग्राम स्तर पर छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज का जाल बिछाने का निर्णय किया है। इसके लिये हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। महोदया, 1948 में औद्योगिक नीति का संकल्प हमारे बीच प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार निर्णय किया गया था कि औद्योगिक विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जायेगा। सरकार ने उसको पूरा किया और औद्योगिक विकास बहुत योजना-बद्ध तरीके से हुआ है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने 1956 में औद्योगिक नीति की घोषणा की थी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रायर्टी सेक्टर में रखा और उसको बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी भी भारत के लिये इसी नीति को चाहते थे क्योंकि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में देहातों में रहती है इसलिये देहात में छोटे-छोटे उद्योग खुलें, घरेलू उद्योग खुलें, कुटीर उद्योग खुलें, सरकार ने इसी पालिसी को मानते हुये, सामने रखते हुये औद्योगिक विकास किया है। इसका सबूत यह है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो पब्लिक सैक्टर के अन्दर सिर्फ पांच कम्पनियां थी और सिर्फ 29 करोड़ रुपया उन पर लगा हुआ था, लेकिन अब पब्लिक सैक्टर में जो कम्पनियां हैं, उनकी संख्या 223 हो गई है और उनतीस हजार करोड़ उन पर खर्च हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र हमारी सफलता का जीता-जागता उदाहरण है।

महोदया, मैं उद्योग मंत्री से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जो प्रशासन है, इसका जो मैनेजमेंट है, वह सही ढंग से नहीं चल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि इसमें काफी घाटा हो रहा है। एक तरफ प्राइवेट सैक्टर दिन दुगुना और रात चौगुना होता जा रहा है और दूसरी तरफ जो आपका

[श्री राम भगत पासवान]

सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें घाटा ही घाटा हो रहा है। इसलिये इसका मेनेजमेंट ठीक ढंग से होना चाहिये और इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी खर्चा किया जाना चाहिये ताकि वह पब्लिक सैक्टर में जो घाटा हो रहा है, वह नही हो। मेरे पास इस घाटे से संबंधित फिगर्ज हैं, 1979–80 में 445 करोड़ रुपया घाटा हुआ था, 1980–81 में 490 करोड़ और 1981–82 में 778 करोड़ रुपये का घाटा पब्लिक सैक्टर में हुआ था।

हमारा आग्रह है कि चूंकि इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसमें घाटे नहीं हों। इसका मेनेजमेंट अच्छा होना चाहिये, इसमें रिसर्च और डेवेलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिये, ताकि पब्लिक सैक्टर में घाटा नहीं हो।

अभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये आपने बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 4038 करोड़ रुपये दिये हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार दिये जायेंगे—जहां पहले यह था कि प्रत्येक प्रखण्ड से 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा, वहां अब एक हजार परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। अब ग्रामीण स्तर पर तो मैं समझता हूं कि रोजगार देने की गारंटी है, लेकिन उस गारंटी के साथ-साथ उसमें बहुत सी खामियां हैं, जिससे कि जनता उसका सही रूप से उपयोग नहीं कर रही है।

अब मैं कर्घा उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कर्घा उद्योग जो है, वह देहात में रोजगार के लिए बहुत मुख्य साधन है, लेकिन आप को मालूम होगा कि इसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। जहां हिन्दुस्तान भर में करोड़ों बुनकर इसमें लगे हुए हैं, वहां उनको जो काटन और सिल्क का सूत सप्लाई किया जा रहा है, उसके भी 25 प्रतिशत दाम बढ़ गये हैं,। इस पर भी वह उनको समय पर नहीं मिलता है। जो इसे सप्लाई करने वाले हैं, वह मुनाफे का अधिक से अधिक हिस्सा ले लेते हैं। बहुत से कर्घा उद्योग बन्द हो गये हैं।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि कर्घा उद्योग पर ध्यान दिया जाए और देहाती एरिया के लिए जो यह रोजी-रोटी का प्रमुख साधन है, वह बंद नहीं होना चाहिए।

दूसरे बहुत से उद्योग-धंधे हैं, जिनमें पूंजिपति लोग क्या करते हैं कि उद्योग-धंधों से काफी फायदा उठा लेते हैं और बाद में वह उद्योग सिक हो जाता है और सिक होकर वह सरकार के ऊपर भार हो जाता है। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि कोई इण्डस्ट्री सिक नहीं होनी चाहिए।

महोदया, अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनको आमदनी बढ़ती जा रही है। समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है और एक तरफ तो कर्घा बुनकर को देखते हैं और दूसरी तरफ टाटा, बिड़ला- डालमियां को देखते हैं। इस आर्थिक विषमता का कहां समावेश होगा, इसको देखकर हम चिंतित जरूर हैं और यह लोग क्या करते हैं कि स्माल सैक्टर में प्रवेश करके सरकार के द्वारा सारा संरक्षण प्राप्त करके जो स्माल सैक्टर की चीजें हैं, छोटे-छोटे उद्योग की चीजें हैं, जो छोटे-छोटे उद्योग वाले बनायेंगे—लेकिन अब इन्होंने उसमें प्रवेश करना शुरू कर दिया है।

मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं कि कौन-कौन सी फैक्ट्रिज हैं जो छोटे-छोटे उद्योग में प्रवेश कर गई हैं और उनको बर्बाद करने पर लगी हुई हैं और इससे कितने कारखाने बंद हो गये हैं। हाउस में

भी चर्चा हुई थी । आई० टी० सी० ने टाप ट्यूल्स इन्टरनेशनल को ले लिया है, इस के बाद विवेनी हैंडलूम्स को अपने हाथ में ले लिया है । उस के बाद टाटा ने सिस्को को ले लिया है और छोटे उद्योगों में जो सामान बनते थे उन को बनाना शुरू कर दिया है । उस के बाद जानसन एंड जानसन ने एथनोर डिवीजन को ले लिया है । इस के बाद सियाराम, जे० के०, बांगुर सारे छोटी इंडस्ट्री में प्रवेश कर गये हैं । छोटे उद्योग धन्धे को प्रोटेक्शन प्राप्त है । आप ने एक्ट पास किया है उस के लिए । लेकिन ये बिना लाइसेंस, बिना परमीशन छोटे उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं । छोटे उद्योग वाले कहां जायेंगे । विनेज स्तर पर जो सामान बना रहे हैं वह कहां जायेंगे । इन पर आप कड़ी से कड़ी निगरानी रखिए । लारसेन टूब्रो और ग्लेक्सो छोटे-छोटे उद्योगों को हड़प रहे हैं । आप ऐसी नीति बनाइये, ऐसा संशोधन कीजिए कि बड़े-बड़े उद्योग छोटे उद्योग को हड़प न सके, उस में प्रवेश न करें । उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । आप समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं—एक तरफ पूंजीपति बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ छोटे-छोटे रोजगार चलाने के लिए पूंजी नहीं मिल रहा है । टाटा, बिड़ला, डालमिया जितनी बड़ी-बड़ी कम्पनी हैं उन को नेशनलाइज कर लिया जाये ।

इस के साथ-साथ इन लोगों को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन मशीन और प्लांट भी हायर-परचेज पर दे रहे हैं । देना चाहिए छोटे उद्योगों को, लेकिन बड़ी बड़ी कम्पनियां सरकारी फेसिलिटी प्राप्त कर रही हैं । यह बन्द होना चाहिए ।

इस के साथ-साथ मैं बिहार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । अशोक पेपर मिल का एक दल हमारे यहां आया है, मंत्री महोदय से भी मिला होगा । इस में 20 करोड़ की पूंजी लगी हुई है । आसाम सरकार और बिहार सरकार दोनों की साझेदारी से यह चलती थी, लेकिन मार्च 1982 में यह बन्द हो गई । तीन हजार मजदूर उस में काम कर रहे थे, लेकिन यह सिक हो गयी है । भारत सरकार से बार-बार आग्रह किया जा रहा है कि इस को टेक-ओवर कर लीजिए, नहीं तो एच० टी० सी० के माध्यम से चलवाइये । उत्तर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है । आप उत्तर बिहार के बारे में जानते हैं, उत्तर बिहार आप का प्रिय प्रान्त रहा है, वहां गरीबी है, प्रकृति के प्रकोप से वह पीड़ित है । अशोक पेपर मिल को आप कृपया अपने हाथ में ले लीजिए जिससे कि जो लोग बेकार हो गये हैं वे फिर रोजी-रोटी पर लग जायें मुजफ्फरपुर में ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : अब समाप्त कीजिए । बिहार पर वह बोल चुके हैं ।

श्री राम भगत पासवान : मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने नहीं कहा ।

मुझे चार-पांच मिनट और चाहिएं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : चार पांच मिनट नहीं दे सकती ।

श्री राम भगत पासवान : उत्तर बिहार बहुत पिछड़ा इलाका है । वहां हर साल बाढ़ आती है । मुजफ्फरपुर में भारत वैगन फैक्ट्री है । वैगन की डिमांड रेलवे की तरफ से आती है । रेलवे वैगनों की हालत बहुत खराब है । अभी वहां डेढ़ हजार आदमी एम्प्लायड है । कम से कम उस को दुगुनी-चौगुनी कर दीजिए । जिस से कि चार-पांच हजार आदमियों को एम्पलायमेंट मिल सके । इसलिए हमारा आग्रह है कि भारत वगन फैक्ट्री जो मुजफ्फरपुर

[श्री राम भगत पासवान]

में चल रही है उस के लिए आप अधिक जमीन एक्वायर कीजिए, उस को डबुल ट्रिपिल कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को एम्पलायमेंट मिल सके। मिथिला हस्तकला केन्द्र में महिलायें ही इम्प्लायड हैं। उद्योग मंत्री जी को मालूम होगा कि अरबों रुपयों का फारेन मनी हम को उस से प्राप्त होता है और यह संस्था विभिन्न जगहों पर चल रही है और उस के प्रोडक्ट की विदेशों में काफी बिक्री है और वहां लोग उस को बहुत पसंद करते हैं। करोड़ों का फारेन मनी हम को उस से प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसकी हालत बहुत दयनीय है। इस के लिये मेरी प्रार्थना है कि एक स्पेशल जांच समिति नियुक्त की जाय और उस की दशा को देख कर उस को पुनर्जीवित करने के लिये जमीन, पूंजी, घर आदि जो भी उस के पास कमी है उस को पूरा किया जाय ताकि मिथिला हस्त कला केन्द्र, जो अविकसित हालत में है, जिस की हालत दयनीय हो चुकी है वह ठीक हो सके। (समय की घंटी) मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): समय बिलकुल नहीं है। आप खत्म कीजिए।

श्री राम भगत पासवान: बिजली बिहार में सप्ताह में 10, 5 घंटे के लिए ही रहती है तो वहां इंडस्ट्री कैसे चलेगी। बिजली का जब तक इंडस्ट्री से कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक वहां की इंडस्ट्री पनप नहीं सकती। वहां इंडस्ट्री चल नहीं सकती। इसलिये बिजली की तरफ आप ध्यान दीजिए। रा मैटीरियल के बारे में कहना चाहता हूं कि बड़े पूंजीपति उस को एलाट करा लेते हैं लेकिन उन के पास फैक्टरी नहीं होती और फिर वे उस को ब्लैक मार्केट कर लेते हैं और जिन के पास फैक्ट्री है उन को रा मैटीरियल नहीं मिलता। इस की आप जांच कराइये और जिन के पास फैक्ट्री न हो उन को यदि रा मैटीरियल दे रहे हैं तो उस को कैंसिल करिये (समय की घंटी) मैं बताना चाहता हूं कि . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): I just want to say that it is not possible if every one of us is going to take so much time. There is a limit,Now there are 15 speakers from the Congress party. If it goes on like this, I just cannot manage time. *(Interrup-*

श्री राम भगत पासवान: अंत में दो तीन बातें कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): यह नहीं होगा। दूसरे स्टेट्स के लोग भी बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही सारी बातें कह लेंगे। आपको मैं एक मिनट दे रही हूं, आप इसी में कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम भगत पासवान: अनइम्प्लायड ग्रेजुयेट्स को जो बैंकों से ऋण मिलता है उस के लिये उन को पैसा देना पड़ता है। वे पैसा कहां से लायेंगे। आप ने उन के लिये 25 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है लेकिन वह ऊंट के मुह में जीरे के समान है। वहां पर करोड़ों लोग अनइम्प्लायड हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप और रुपया सेल्फ इम्प्लायमेंट स्कीम के अंतर्गत अधिक राशि दीजिए ताकि लोगों को कुछ मदद मिल सके। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन गरीबों में जो अनइम्प्लायड महिलायें हैं उन को यह लोन अवश्य

मिलना चाहिए, जो पावर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उन को यह सहायता मिलनी चाहिए । उन को आप इंप्लायमेंट दीजिए । मैं अंत में आप का आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज उद्योग मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेने के लिये आप ने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं । देश की प्रगति के लिये कृषि के विकास के साथ-साथ उद्योगों का विकास बहुत आवश्यक है । आज देश के व्यापक बेरोजगारी की समस्या को नये नये उद्योग स्थापित कर के ही दूर किया जा सकता हैं। सौभाग्य की बात हैं कि उद्योग मंत्रालय से जिम्मेदार विभाग का भार एक ऐसे कर्मशील नेता के हाथ में है जो आदरणीय पं० जवाहरलाल नेहरु जी के समय की घोषित नीति के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एक नयी दिशा दे रहे हैं जिस से पिछड़े क्षेत्रों में विश्वास हो गया है कि उन का औद्योगिक विकास होगा।

गत वर्ष पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये शिवरामन कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय हो जाने तक पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर उद्योग रहित जिलों में अधिक निवेश प्रेरित करने के लिये विद्यमान योजनाओं में संगत संशोधन किये जाने का निर्णय एक ऐसा निर्णय है जिससे औद्योगिक विकास के फल उन क्षेत्रों में जहां के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन के क्षेत्र में उद्योग लगेंगे, उन को रोजगार के अवसर उत्पन्न होने लगे हैं तथा विकास हो रहा है। उद्योग मंत्रालय ने उद्योग रहित क्षेत्रों की संख्या 118 से बढ़ाकर 131 कर दी है । इस प्रकार के क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु केन्द्रीय सहायता की राशि 15 प्रतिशत या 15 लाख से बढ़ा कर 25 प्रतिशत या 25 लाख कर दी है जिससे कि इस प्रकार के क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को प्रेरित किया जा सके ।

4 P m

इसी प्रकार आपने, अन्य श्रेणी के क्षेत्रों में जो सहायता या राहत घोषि की है, उससे उन क्षेत्रों मे उद्योगों का भी विकास होगा । इसके साथ ही हमारे उद्योग मंत्री जी ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से रियायती दर पर वित्तीय साधन दिलाने की योजनाएं तैयार कराई है जिनसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास संभव हो सकेगा ।

श्रीमन्, दुर्भाग्य से आज यहां पर सुरेश कलमाडी जी नहीं है । मैंने कल उनको देखा था और प्रश्नोत्तर काल में उनका रूप देखा था । जब वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध करने के लिए आमादा हैं । वह जहां के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं । हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी बहुत से क्षेत्र या जिले हैं जहां उद्योग कम है, लेकिन वह पूना के रहने वाले हैं । बम्बई, थाना से उनका वास्ता है । इसलिए मैं महाराष्ट्र के आंकड़े आपको देना चाहता हूं । वे जिस क्षेत्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में' वहां पर कुल उद्योग 12300 हैं जिनमें से बम्बई में 6057 लगे हैं जो कि कुल महाराष्ट्र के उद्योगों का 48.50 प्रतिशत है । थाना में 1312 उद्योग लगे हैं जो कि कुल महाराष्ट्र का 10.61 प्रतिशत है । पूना में जहां के वे रहने वाले हैं वहां पर 1161 उद्योग लगे हुए हैं जो कि महाराष्ट्र का 9.39 प्रतिशत है । साथ

[श्री घनश्याम सिंह]

हो महाराष्ट्र में भी मराठवाडा के 5 जिले ऐसे हैं जहां केवल 3 प्रतिशत उद्योग लगे हुए हैं । तो सुरेश कलमाडी जो जिस क्षेत्र की बात कह रहे थे वहां विकास हो चुका है । मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र का विकास हो चुका है वहीं पर उद्योग लगाने की मांग करना न तो न्यायसंगत है और न ही अच्छा है । जब तक छोटे उद्योगों को पिछड़े हुए इलाकों में नहीं देंगे जहां उद्योग नहीं लगे हैं तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें । कुछ सदस्यों ने कहा था कि माननीय उद्योग मंत्री जी उद्योगपतियों पर दबाव डालते हैं और पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग लगाने के लिए कहते हैं । मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा किया या नहीं, लेकिन मैं उनसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि वे उद्योगपतियों को प्रेरित करें, उन पर दबाव डालें कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपने उद्योग लगायें जिससे कि उन क्षेत्रों का विकास हो सके । इसलिए मैं चाहूंगा कि कुल 131 जिले ऐसे हैं जो कि उद्योग रहित हैं, अतः उद्योगपतियों पर दबाव डालकर उन सभी जिलों में उद्योग लगवा देंगे तभी आपकी औद्योगीकरण एवं देश के समुचित विकास की कल्पना पूरी हो सकेगी ।

श्रीमन्, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने विभिन्न प्रकार के लाइसेंस पिछड़े हुए क्षेत्रों के नाम से ले लेते हैं और बाद में उनको अपनी सुविधा से दूसरी जगह स्थानान्तरित करा लेते हैं । आपने ऐसे लाइसेंसों को स्थानान्तरित न करने की शर्त लागू की है और ऐसा करने पर पाबन्दी लगाने की कोशिश की है, इसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को जहां के लिए स्वीकृति दें, वहीं पर उनको स्थापित करवायें । उनको स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा वहां उद्योग नहीं लग पायेंगे ।

श्रीमन्, उद्योग मंत्रालय के बारे में हमारे दोस्त कह रहे थे कि विकास नहीं किया । श्रीमन्, पिछले आंकड़े मैं बताना चाहता हूं । 1979 में उद्योग मंत्रालय ने कुछ क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए जहां 550 आशयपत्र दिए थे उनमें से पिछड़े क्षेत्रों के लिए 244 आशयपत्र थे जब कि उसके मुकाबले में पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिशत 44.36 था विकसित क्षेत्रों की तुलना में । इसी तरीके से 1982 में आपने जो लाइसेंस दिए हैं उनकी संख्या 1043 है जिनमें से 583 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं जो कि कुल लाइसेंसों का 56 प्रतिशत के करीब है । इसी तरीके से 1981 में आपने कुल 1055 लाइसेंस दिए जिनमें से 649 लाइसेंस आपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिए और इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़कर 61 परसेंट हो गया है जिससे यह दिखाई पड़ता है कि आपकी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति पिछड़े हुए क्षेत्रों को बढ़ावा देने की है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रतिशत जनता पार्टी में पिछड़े हुए क्षेत्रों का 44 प्रतिशत था वह आपने 61 प्रतिशत पर ला दिया है । मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी योजना बनायें कि 1 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योग आप उस समय तक पिछड़े क्षेत्रों में ही लगायें जब तक कि आपके पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिशत 75 तक न हो जाए ।

कल हमारे मित्र सुरेश कलमाडी साहब बोल रहे थे । उन्होंने कहा था कि उद्योग मंत्री ने अपना पूंजीनिवेश बढ़ाने के लिये जो विदेशों से कोलाबरेशन किया है,

150 उद्योगों ने किया है । उन्होंने यह भी कहा कि उसमें से 100 उत्तर प्रदेश में हैं । मुझे उनकी अक्ल पर रहम आता है कि कहां से ऐसी झूठी खबरें लाने की कोशिश करते हैं और सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जबकि यह इसके बिल्कुल विपरीत है । उत्तर प्रदेश में 11 उद्योगों से कोलाबरेशन हुआ जबकि इनका कहना है कि 100 का हुआ । इस सदन में भ्रम फैलाने का यह प्रयत्न करते हैं । अगर वह आज होते तो समझ में आता कि कहां पर सत्यता है ।

देश के विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है । उद्योग मंत्रालय ने उद्योग अधिनियम में जो संशोधन किया है काफी महत्वपूर्ण है । पूर्व में लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली आरक्षित वस्तुओं की संख्या 843 से बढ़ा कर 872 करना एवं सरकारी क्षेत्रों की खरीद के लिये वस्तुओं की संख्या 384 से 404 करना प्रभावी कदम है । इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि माननीय उद्योग मंत्री जी इस प्रकार के आरक्षणों का दूना निरीक्षण करा कर और बढ़ाने के बारे में विचार कर लें ।

लघु उद्योग क्षेत्र में पिछले वर्षों में अच्छा कार्य हुआ है । क्योंकि हम लोगों ने 1979-80 में 3.92 लाख उद्योग पंजीकृत किये थे जो 1982-83 में बढ़ कर 5.96 लाख हो गये । उत्पादन मूल्य जो 1979-80 में 21 हजार 635 करोड़ का था वह बढ़कर 1982-83 में 1935 हजार करोड़ हो गया । यह तरक्की हुई उद्योग के मामले में । इससे लगता है लघु उद्योगों में कितना विकास हुआ है । गत वर्ष 82-83 में 79 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया । उत्पादन आरक्षण एवं लघु उद्योगों के विकास पर संतोष किया जा सकता है परन्तु इस क्षेत्र में उद्योगों को और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि देश की तरक्की कुटीर एवं लघु उद्योगों से ही संभव है । आज जापान की औद्योगिक क्रान्ति में उद्योगों की प्रमुख भूमिका है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) पीठासीन हुये,]

मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि देश के नये उद्यमियों को विदेशों में स्थापित सफल औद्योगिक इकाइयों के दौरे करने के लिये योजना बनाकर क्रियान्वित करने का कष्ट करें ।

हुकमदेव नारायण यादव जी यहां पर नहीं हैं । वह कल बोल रहे थे । मैं बताना चाहता हूं कि गांधी जी बड़े उद्योग अथवा मशीनरी द्वारा काम किये जाने के विरुद्ध नहीं थे । परन्तु वह चाहते थे कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिले जिससे ग्राम स्वावलम्बी बन सकें ।

विदेशी माल का बहिष्कार करते समय भी उन्होंने कहा था कि जो चीज हम अपने देश में बना सकें और वह अनिवार्य हो तो दूसरे देशों से प्राप्त करने में हम संकीर्णता नहीं दिखानी चाहिये । मैं समझता हूं यह बुनियादी नीति है जिनका अमल हमको करना चाहिये । आज हमारी नीति भी यही चल रही है । इसलिये हमने गांधी जी की नीति से कोई विरोध नहीं किया है ।

गांधीजी बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं थे । उनका कहना था जो चीज हम ग्रामीण अवस्था में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उन्हें हमें बड़े उद्योग लगा कर पूरा करना चाहिये ।

गांधी जी चाहते थे कि हम ऐसे उद्योग लगावें जिन्हें ग्रामीण व्यक्ति अपने घर पर ही स्थापित कर सकें । इस प्रकार के उद्योगों से वह गांव को स्वावलम्बी बनाना

[श्री घनश्याम सिंह]

चाहते थे जिससे ग्रामीण व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिये शहर की ओर न दौड़ना पड़े । इसी प्रकार के उद्योगों से ग्राम स्वावलम्बी बन सकते हैं । उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र में खादी के अतिरिक्त 25 अन्य उद्योगों को आरक्षित कर रखा है परन्तु इन उत्पादित वस्तुओं को भी कुछ मझले एवं आर्गनाइज्ड सेक्टर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिससे इन उद्योगों के बढ़ावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । (समय की घंटी) मान्यवर, शायद आप मेरे साथ ठीक से न्याय नहीं कर पा रहे हैं । आपने सात मिनट में ही घंटी बजा दी । मेरे पूर्ववक्ता आधा-आधा घंटा बोले हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : आप दस मिनट बोल चुके हैं । एक-दो मिनट में खत्म करिये ।

श्री घनश्याम सिंह : मैंने अभी तो अपने प्रदेश की एक बात भी नहीं कही । मैं अभी तो मंत्रालय पर ही बोल रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): ठीक है आप शुरू करिये ।

श्री घनश्याम सिंह : उत्पादन मूल्य में और रोजगार दिलाने में आपने बहुत तरक्की की है लेकिन मैं इस संबंध में आंकड़े न दे कर सदन का समय नहीं लेना चाहता ।

मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि देश में आपने काफी तरक्की की है लेकिन उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य अच्छा नहीं रहा है । मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि इन्होंने मेरे गृह जनपद अलीगढ़ में लगभग 6 लाख के निवेश से उद्योग स्थापित किये जो पर्याप्त नहीं हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए ।

गांवों में रहने वाले बढ़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, बुनकर, रस्सा बंटने वाले इत्यादि प्रकार के व्यक्तियों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जा रही है जिसका व्यापक असर पड़ रहा है । परन्तु इसमें कुछ लोग मिलने वाली सहायता का अपव्यय कर रहे हैं तथा कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे रोकने के लिये वे सख्त कदम उठायें ।

हमारी आदरणीया प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1983 को लाल किले की प्राचीर से देश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को 25,000 रुपये तक की सीमा तक के उद्योग लगाने हेतु वित्तीय सहायता दिलाने की घोषणा की थी । यह गत वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि थी । सन् 1983–84 के वर्ष में 2,30,000 प्रार्थना पत्र दिये गये और 2,18,000 नवयुवकों को बैंकों से ऋण स्वीकृत किये गये । मैं चाहूंगा कि जब सरकार इन लोगों को उद्योग चलाने के लिये ऋण दे रही है तो मैं उद्योग मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो 25 हजार रुपये आप रोजगार के लिये दे रहे हैं उनको कुछ प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी कर दें जिससे इनको दिये गये धन का सदुपयोग हो सके और राष्ट्र का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके ।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुछ उद्योग तो विभाग ने स्थापित किये हैं और कुछ राष्ट्रीयकरण के द्वारा प्राप्त हुये हैं । मैं इनके विषय में ज्यादा न कहते हुये सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इन उद्योगों के कार्यकलाप में अगर कोई कमी आती है तो उद्योग मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे प्रबन्धकों की तरफ भी ध्यान दें और यदि उनमें कोई कमी पायी जाती है तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्यवाही करें । लेकिन जो प्रबन्धक अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार भी दें ।

आज हमारे देश को एच० एम० टी० एवं बी० एच० ई० एल० जैसे उद्योगों पर गर्व है। इनके उत्पादन ऐसे हैं जिनको लोग पसन्द करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो और जनता की जो मांग है उसका वे उत्पादन करें और उनको प्रसिद्धि मिले। हमारे कुछ मित्रों ने ऐसे उद्योगों के बारे में कहा जिनमें हानि हो रही है। एक तरफ तो यह दबाव डाला जाता है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और जिन उद्योगों में अनियमिततायें हैं, भ्रष्टाचार हैं और कुप्रबन्ध है उनको सरकार अपने हाथ में ले ले और दूसरी तरफ इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे उद्योगों को ठीक करने में कुछ समय लगता ही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन उद्योगों को चलाये ताकि वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको रोजगार मिल सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बीमार उद्योग हैं उनसे लाभ प्राप्त करने में कुछ समय तो लगता ही है। आप इन उद्योगों के विकास के लिये एक समयबद्ध योजना बनायें जिससे एक निश्चित समय के अन्दर इन उद्योगों से लाभ मिलने लगे और ये उद्योग अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर सकें।

गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में काफी हालत में सुधार हुआ है। गत वर्ष उद्योगों के क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इससे पूर्व वर्ष में इसी समय में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आज वह ज्यादा है। यह प्रगति दिसम्बर, 1983 में 5.9 प्रतिशत, जनवरी, 1984 में 8.8 प्रतिशत और फरवरी में 12.3 प्रतिशत हुई है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। थोड़े समय के बाद ही इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आने लगेंगे। आधारभूत क्षेत्र के उत्पाद में जनवरी से मार्च, 1984 में गत वर्ष जनवरी से मार्च, 1983 के मुकाबले 11.8 प्रतिशत की वृद्धि एक अच्छी और संतोषजनक कार्य है। विद्युत उत्पादन में हमने उत्पादन क्षमता का विकास तो कर लिया है; परंतु उत्पादन के स्तर में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब प्राइवेट सैक्टर में टाटा के पावर हाउस में 90 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग हो सकता है तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में उत्पादन बढ़ाना होगा। जहां पर बेसिक गलती है उसको ठीक करना होगा तभी हम इस देश में विद्युत का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलता पर हम निश्चय ही गर्व कर सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारी सीमेंट उत्पादन क्षमता 242.90 लाख मी० टन थी। योजना के अन्त में यह परिकल्पना की गई थी कि क्षमता 430 लाख मी० टन हो जायेगा, परन्तु अब आशा है कि योजना के अन्त में यह क्षमता 442.50 लाख मी० टन हो जायेगी। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। छठी पंचवर्षीय योजना में हम इस लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। सीमेंट के उत्पादन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है।

मेरा इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि उपभोक्ता को सीमेंट बोरियों में मिलता है। लेकिन वह बोरियों में रिसाव होने के कारण पूरा नहीं मिलता है। इसलिये सीमेंट उद्योग में निश्चयपूर्वक ऐसी बोरियां इस्तेमाल करवायें जिससे रिसाव की कोई गुंजाइश न हो। (**समय** की घंटी) दो मिनट में खत्म किये देता हूं।

हमारे देश में उद्योगों का रुग्ण हो जाना एक विकराल समस्या है। यह सत्य है कि रुग्ण संस्थाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है परन्तु

[श्री घनश्याम सिंह]

इकाई स्थापित होने से रुग्णता का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये तो प्रतिशत रुग्णता में गिराव आया है । इस विषय में हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे उद्योग को रुग्ण होने से पूर्व ही पता लगाया जाय तथा उन कमियों को दूर करने के उपाय किये जायें । मेरी राय में उद्योगों के रुग्ण होने के तीन प्रमुख कारण हैं : (1) प्रबन्ध में अव्यवस्था एवं वित्तीय दुरुपयोग, (2) विद्युत की कमी, और (3) उचित समय पर वित्तीय सहायता न मिलना । बहुत से उद्योग घराने अपने उद्योगों में से धन निकालते रहते हैं तथा बाद में रुग्ण घोषित कर बन्द कर देते हैं तथा इन चालाक उद्योगपतियों का मजदूर संगठनों से भी संबंध हो जाता है । उनके द्वारा सरकार पर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने हेतु दबाव डाला जाता है । इस तरह की गतिविधियों को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिये तथा ऐसे उद्योग घरानों को आर्थिक अपराधी घोषित करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये ।

विद्युत आपूर्ति न होने के कारण भी उद्योग रुग्ण हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़वायें । आपके द्वारा कैप्टिव जेनरेटरों पर आर्थिक सहायता दिया जाना एक सराहनीय प्रयास है । मेरी राय में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन भी इसके लिये किया जाना चाहिये ।

वित्तीय संस्थायें जितना प्रचार सहायता दिये जाने का करती हैं उतना कार्य नहीं करती हैं । मुझे उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक हैंडलूम कम्पलेक्स की स्थिति के बारे में जानकारी है । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हैंडलूम कम्पलेक्स वहां स्थापित किया । जिसमें वर्किंग कैपिटल 10 प्रतिशत के मार्जिन पर पंजाब नेशनल बैंक को देना निश्चय हुआ । परन्तु इस बैंक ने आज तक वहां के बहुत से उद्योगों को ऋण नहीं दिया जिससे उस कम्पलेक्स की इकाइयां रुग्ण हो रही हैं । मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को इस विषय में लिखा है परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करने का कष्ट करें ।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान अलीगढ़ की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अलीगढ़ तालों की नगरी के नाम से विख्यात है । वह उद्योग वहां पर कुटीर उद्योग के तरीके से अपनी पुरानी परिपाटी में चल रहा है । आज देश एवं विदेशों में बहुत तरक्की साइंस और टेक्नोलाजी में हो गई है जिसके कारण हमारे यहां के तालों की स्थिति में कमी आ रही है । इसलिये मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा अलीगढ़ के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़ में स्थापित करा दें जिससे वहां के कारीगर दक्ष हो सकें ।

महोदय, माननीय उद्योग मंत्री 1976-77 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । उस समय आप हमारी माननीया प्रधान मंत्री को लेकर सलेमपुर स्थान पर गये थे । और वहां पर पैट्रो केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना की घोषणा की थी लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों की भूमि अधिग्रहीत कर ली है तथा अन्य डेवलपमेन्ट उस भूमि पर कर दिये हैं लेकिन हमारे जनपद का दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पेट्रो केमिकल कम्पलेक्स का काम नहीं हो सकता है । जिन लोगों की भूमि ली गई है न उनको मुआवजा दिया गया है और न कुछ और किया गया है । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे

उद्योग मंत्रालय पर किसी तरह से दबाव डालें और जो उन लोगों को मुआवजा मिलना है उसको तुरन्त उनमें वितरित कर दें। यह काम तुरन्त किया जाना चाहिए। वहां लोगों में निराशा फैलती जा रही है। अतः इस कम्प्लैक्स को वहां तुरन्त स्थापना कर लोगों की निराशा को दूर करने का प्रयास मंत्री महोदय करें।

अन्त में मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि आप शीघ्र ही इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करा दें जिससे कि शीघ्र ही वहां का विकास हो सके। मेरा अनुरोध है कि उन क्षेत्रों में अगले वर्ष तक जो छोटे उद्योग हैं वह हम स्थापित कर दें जिससे कि हम वहां लोगों को यह कह सकें कि हमने इस क्षेत्र में इतनी तरक्की की है। प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहां पर छोटे उद्योग लगाने के पश्चात्, जब यह कार्य खत्म हो जाय तो फिर तालुका स्तर पर और फिर तहसील स्तर पर उद्योग लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि देश का सम्यक विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं गत वर्ष उद्योग मंत्रालय के कार्यों पर संतोष व्यक्त करता हूं और

SHRI BIJOY KRISHNA HANDIQUE (Assam): Mr. Vice-Chairman, while discussing the working of the Ministry of Industry, I would like to raise an important matter which concerns the priority sector of our national economy, that is, the plight of the tea industry, the second biggest foreign-exchange earner. It is not only a matter of national importance, but the prosperity of my State, and for that matter the entire North-Eas-tem region, depends upon the thriving of this industry. Sir, I have raised this point particularly because, as you know, Assam is in the nadir of industrial backwardness. At the moment, we have not seen any new industries coming up. I will come to this later on. That is the reason why I have raised this issue, I have raised this question of the development of the tea industry, because, this industry has to be salvaged, has to be rescued. Unless some firm steps are taken immediately to improve things in the industry, I am afraid, this industry will drift into a mess.

At the very outset, let me make one point clear. It has been the practice of the industry to blame the Government, pass the buck to the Government for all the ills. While, it is true that the Government does not have a well-defined tea policy, as it has had in the case of the other sectors of the national economy, such as, steel, coal; oil etc it is also true that the industry in its town has not done much even within its limitations to make things better, at least to convince the Government that it has done its part and now it is for the Government to fulfil its obligations.

Sir, I now come to the question of modernisation. The current Budget and the Budget of 1983-84 have laid great emphasis on modernisation of plant and machinery. The Government is convinced that obsolete plant . and machinery in traditional industries is the cause for industrial sickness. We have before us the said spectacle of the jute and the textile industry where sickness has been growing over the years, due to the apathy of the companies, to modernise their plant and machinery. I hope, the Government will take steps to see that these industries get soft loans from the IDBI to help modernise their Industry, their plant and machinery which are obsolete at the moment. I

[Shri Bijoy Krishna Handique

have raised the case of the jute and the textile industry because they are the eye-openers, or, at least, they should be the eye-openers to the tea industry. • In a large number of tea estates, the concept of ploughing back the profits for further investment has long lost its relevance. This is a vicious circle. The tea gardens take the plea that they run into losses because the industry is highly taxed, and they are not able to make profits and that, therefore, they have nothing much left to be ploughed back. But it is also a fact that there are well-managed tea gardens. This repudiates such a plea and corroborates the fact that despite the oft repeated, oft talked about constraints, these gardens have been on a sound footing. If it is possible in the case of some tea gardens, why it should not be possible in the case of others?

However, I would - like to impress upon the hon. Minister that tea deserves special consideration and reexamination in the context of fiscal reliefs. Of course, one thing should be borne in mind here. We cannot ask for any reduction in. duty. The hon. Minister will not agree to this because it is a rather difficult proposition. What I would suggest is that the existing subsidies for . developmental activities should be more purposeful. The plantation and rehabilitation subsidies which have already been provided have been very helpful to the industry in the State. But what I would suggest is that the amount needs to be increased in view of the escalation-in expenditure. I can give you an idea. The cost of plantation in new areas is exorbitantly high. . It will be in the region of . Rs. 50,000 per hectare. In the case of replantation it is slightly less costly, but it will also be in the region of Rs. 35,000 to 40,000 per hectare. We have also to take into account the long gestation period. The other fact is, because of continued drought condition particularly in some drought-prone areas of Assam, tea production has suffered a lot You know, Sir, Assam has 769 tea gardens and 1,95,400 hectares of land are under tea cultivation. So, Sir, irrigation facilities have to be arranged in a big way. It is also true that in the drought-affected area even the source of water is a problem, but this problem can be overcome if the case of tea gardens is kept in mind while drawing up plans for irrigation for agricultural purposes. About the finances I believe, financial institutions like NABARD can' be approached. They can help in a big way so far as finances are concerned. We should also impress upon the Industry Ministry that the improvement in production is not a one-sided traffic. Government cannot expect the production, to go up of its own if the tea industry is insisted upon ploughing back its funds and no> financial assistance is offered to it. Of course, I understand when financial assistance is given there is a risk of its being misused. There have been cases where the financial assistance has been spant for rehabilitation and for purposes other than tea plantation. For that purpose a machinery can be evolved to check whether the financial assistance has been utilised properly or not.

The tea industry should also be made to feel that the price of tea being firm in the last few years, they should also be prepared to spend on the imports. I do agree that weighed down by massive taxation rate to the tune of 68.1 per cent which is combination of both the Central Government and the State Government taxes, payable under the Central excise taxes and the State agricultural income taxes, the existing benefits available to the industry are indeed inadequate. For instance, while the costs of exten- sion, plantation and replanting have been increasing year after year, the admissible limits on account of development allowances and replanting subsidies have been placed at a very

unrealistic level. The purview of some other incentives for which the tea industry does not qualify at pre sent, such as agricultural develop ment allowances, etc., should be ex tended to tea a_s the main operation of this industry is agricultural in na ture.

Another step is the creation of the capital fund. The tea garden. should be allowed to create a reserve or development fund or both out of its own profits and this proposal has been lying pending with the Commerce Ministry for clearance.

Now 1 come to the most urgent task, that is, how to meet the growing domestic requirements and to increase the export earnings. The Government must give due attention to a massive increase in production. Otherwise, I am afraid a time will come when there -will not be much surplus tea availably to meet the export obligation. There is average consumption growth of 12 million kg. every year if India's share in the export market is to be maintained at the current level of 28-1 per cent. tea export will have to go up to 321.4 million kg. in 1990 from 241.6 million kg- in 1980. At present the production is 575 million kg. It may be 565 million or 575 million on an average. In order to reach this target tea industry has to produce at least 960 kgs. of tea. In 1976 the Ministry of Commerce in consul-tation with the industry and Tea Board set a target that by .2,000 A.D. the production has to reach 1.000 million kgs of tea. Sir. the annual domestic consumption has been reckon-ed at 500 million kilograms by 1990, taking into account a population increase of 10 million every year and the per capita increase in consumption of 10 grams. This means an additional production over the next 16 years of between 385 to 435 million kilograms from the level of present 565 to 575 million kilograms of tea. In order to meet the requirements of both the domestic market as well as exports, tea production has to be increased *by* 22 million to 25 million kilograms every year. But the greatest hurdle is the non-availability of land. Not that land is not available, but the land is not in possession of this industry. An estimate shows that a yearly addition of 2000 hectares of new area under tea, would increase the crop by 90 million by 2000 AD. It is just a survey report that I am quoting from. Intensive cultivation and new plantations will contribute 125 million kilograms of additional crop which will raise the total crop to 70l million kilograms, but will yet fall short of the targeted figure by 174 million kilograms. Now the question comes: how to get this 174 million kilograms? And for that crop has to be harvested for replanted area. To achieve this short fall of 174 million kilograms. It would be necessary for 1,40,000 hectares area to be uprooted and 7777 hectares to be uprooted and replanted every year during the next 16 years. So, Sir, this is the magnitude of the problem and I do hope the Government would apply its mind to it. It is not enough to ask the industry to boost up production and exports unless major constraint like land is removed.

Sir, before I conclude I would refer briefly to the much needed thrust to science and technology in tea. Re search and Development, I am afraid> are in doldrums for more than a de cade. There are two institutions— Tocklai Experimental Station and Upasi in South. Both are under the Commerce Ministry. Since the take' over of Tocklai by TRA, it has not done anything significant in the field of research and development work It was in 1931 that the CTC processing was first evolved and that was when it was not under TRA. Since the take-over it has not done much, though occasionally a few proceeses have been evolved and a few machineries have been designed and developed at the station. i Particularly I would mention the

[Shri Bijoy Krishna Handique]

continuous withering machine developed by a local engineer, Mr Tarun Bar-ua.

Then, Sir, it is quite interesting that there is another Central Government organisation—the Central Food and Technology Research Institute—which has done useful and suitable research work. It has developed indigenous technology for making plants for manufacturing instant tea and pioneering and evolving a new chemical from the tea waste to increase the yield of the tea bushes.

These are some of the facts that 1 have to place before the hon. Minister of industry with the hope that he will apply his mind to them and also to see that for the entire rgion a master plan for industrialisation is prepared. Otherwise in spite of our promises we have not been done much to industrially develop this area and since it is industrially not developed, at least the tea industry which is the only industry at the moment which is capable of thriving should be helped by Government. Thank you.

SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH (Manipur); Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all I take this opportunity of thanking you for allowing me to speak during the discussion on the Ministry of Industry. Coming as I do from a very small State, the State of Manipur, about which I shall deal a little later in the course of my speech. It s true that our country has seen an all-round development and progress in every aspect—be it in the field of agriculture, be it in the field of power generation, be it in the field of creating irrigation potential, be it in the field of industries, which is, of course the subject-matter that we are discussing in the House today. It is also true that the rate of inflation has been checked to a single digit, as was announced by the hon. Finance Minister the other day. This in itself is a phenomenal achievement. It is also true that the Department of Industrial Development has been working and is mainly responsible for formulation and implementation of policies for industrialisation in the country for fixing various targets and priorities in the Five-Year Plans. Sir, it 5s also true that several measures have been taken over the years to remove various bottlenecks that exist in the implementation of many of the policies under the Ministry of Industry. It is also true that the small industry sector has a significant role in the realisation of the socio-economic objectives like removal of regional imbalances, which I shall deal immediately after this. Then it is also true that a very important scheme, the scheme of self.employment, for the educated unemployed has been taken up and about 2 to 2.5 lakhs of the educated unemployed have been given employment and serious endeavours are being made to look into this problem. The fact that the Government of India and the Industry Department have taken serious note of the development of industry is borne by the fact that it has been included in the 20-point programme Point No. 18 clearly states: Liberalisation of investment procedures and streamlining industrial policy to ensure timely completion of projects; also for providing faclities for the growth of handicrafts and handlooms and small and village industries, and to update their technology. Now this is a point which will be very beneficial and important in a small State like ours.

Sir, much has been talked and there have bten references yesterday *and* to day to the claims coming from various States that States like Maharashtra or Bihar or Uttar Pradesh are industrially backward. But I do not think we can even find words within , the realm of English language for a State like Manipur cannot even be termed as a 'No Industry District' area. It is one of those rare things. Now we do not have even a single industry worth the name, except one or two industries about which I shall make a reference a little later. Much of. the industrial development has been confined, it is true to the northern,

western'and some southern and eastern parts. But most of the northeastern sector hag been neglected.

The very fact that the Plan allocation of the Slate of Manipur from 1952 to 1980 is much lower than that for the period starting from 1979 to 1984, that is to say that the entire Plan allo cation of the State from the First Five Year Plan which started in 1952 till *the* ending of the Fifth Five Year Plan in 1979 is much less than we are given during the Sixth Five Year Plan ending in 1904 or 1985, clearly shows that the area has not been properly looked into. Of course, efforts are being made and efforts have been made to look into it. It is, of course, being done is Lome by the fact that the present Plan is adequately looking into it. Therefore, much more efforts are ne eded towards the overall development of this area.

For this, Sir, I would like to suggest a few things for the industrial development of the State:

A task force be constituted in the State so that indigenous factories or mills or industries that can be set up where there are infrastructural facilities available, can be set up sooner or later in those areas. I can site the example of the cement factory which is our North - Eastern Council project. But it is still at a take-off stage. This has been cleared, but nothing has been done as yet.

The spinning mill which was started about four years back is a dead mill. It had contemplated a capacity of 25,500 spindles. We do not even have a four figure sum in that. Serious efforts will have to be made in this regard because Manipur is famous for its handicrafts and hand-looms.

Then, there is the starch and glucose factory. I do not think we have any of this type in the entire North-Eastern region. There has been a serious attempt to get it started. The project report has been prepared and submitted by the NETCO. Clearance has been given by the Planning Commission. But nothing has been done. So, I would request the hon. Industry Minister to seriously look into it and at least include this in the Seventh Five Year Plan.

Then the sugar mill which was con-templated and supposed to have started in Kabow-wakching has no taken off. Clearance was given by the Planning Commission. Its capacity is 2.5 metric tonnes per day crushing capacity. But nothing has yet been done in this regard

Then semi-mechanised brick-kilns. This is a suggestion, Sir, which I would like to make on the floor of the House, because Manipur and probably Mizoram are the two areas in the North-Eastern region where the building materials are the costliest in the entire country. The cost of one brick in Manipur, for example, is anything between Re. 1 and Re. 1.50P, of course depending upon the quality. But the worst type of brick available will cost Re. 1 in the State, and of course the highest would be Re. 1.50 P. So, it will be absolutely difficult for an ordinary citizen to construct a house, with so much of cost. It is here that I would like to suggest that we should go in for a semi-mechanised brick-kiln in the public sector. The Minister of Industry would seriously look into it.

Sir, then, there is much talk about the paper mill. Two out of seven districts in Manipur grow a particular type of bamboo.

The entire Western district and half of the area of the South district of Manipur they grow a particular type of bamboo. We have been requesting the Union Government par-ticularly the Ministry of Industry and Planning Commission to set up a paper mill because this will not have

{Shri Jaichandra Singh] any ecological imbalance as it is . based on bamboo and not a tree, based industry. This is again a matter which has been long pending before the Union Government and the Ministry of Industry would do well to look into it.

Sir, it is needless for me to suggest the possible industries in Manipur. That is why a little earlier I had sug- . gested to form a special task force to lock into all these things. "

Then, my second suggestion would be to include or to establish a branch institute with associated work facilities. This branch institute has been established in certain areas but I believe no attempt has been to establish it in Manipur. Therefore, I would request the Hon'ble Minister for Industry to establish a branch institute in Manipur. There is other correlated matter i.e. establishing of more banks in rural areas in Manipur and hilly areas. It is very difficult for any of the hilly man in our area to enjoy the fruits of the banking. Because they do not have any branches there not even a divisional headquarter and not even a sub-divisional headquarter has a bank branch. This is another area where I would request the Hon'ble Finance Minster to look into it.

Then, I would also request the Central Government particularly the Mini-try of Indusrtry to identify the indigenous skill to suit the local conditions or to increase the inflrastructural facilities that are available in the State.

Then last of all, something should be done in regard to the transport subsidy I know that much has been done but a lot more needs to be clone in this regard.

Then, Sir, the State does not have a rail link. The nearest train from the capita} city of Manipur is about 200 kilometers. I request the Union Government earnestly to consider extending the transport subsidy scheme in our State.

Last but not the least, special schemes must be immediately promoted or looked into for promoting hand-looms and handicrafts. So, with these few words I conclude and I thank you for giving me an opportunity to speak in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI). Now, Shri Sohan Lal Dhusia, please.

श्री सोहन लाल धूसिया (उत्तर प्रदेश) : अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह किस की दूरदर्शिता थी कि जिन्होंने आज हिन्दुस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय नक्शे पर ला खड़ा किया है और यहां पर इंडस्ट्रीज चलती हैं और बनाई जाती हैं, अब तो हमारा देश संसार के कम्पीटीशन में आने लगा है यह सब हमारे कांग्रेसी नेताओं की देन है । इंडस्ट्री के मामले में देश में इन्होंने तरक्की की है लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर किसी की नजर नहीं पड़ी । इत्तफाक की बात है कि श्री तिवारी जी यू. पी० के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । यह जानते हैं कि बलिया से लेकर गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर आदि जगहों पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो खाली शुगर मिल हैं जो तीन महीने की है । यह सीजनल है । आपसे यह पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां के लोग जबतक तेलंगाना जैसी हरकत नहीं करेंगे तब तक यहां पर गवर्नमेंट की नजर नहीं पड़ेगी ? हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट आसानी से चले। यह सही है कि यहां के लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और

इसीलिए अंग्रेजों ने इसको बैकवर्ड रखा है। वही नजरिया आज अपनी गवर्नमेंट का भी हो तो यह अच्छी चीज नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिन जिलों का मैंने नाम लिया है, गवर्नमेंट उनका सर्वे कराये। यहां पर बहुत अधिक पापुलेशन है, रा-मेटिरियल भी अधिक है। लेकिन फिर भी वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। यह किस की गलती है। क्या यह वहां के लोगों की गलती है या आफिसर्स की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है, मिनिस्ट्री की गलती है या तिवारी जी की गलती है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसका फैसला करे कि यह कैसे हो रहा है। हम इन शब्दों के साथ कहना चाहेंगे आपको एग्जाम्पल देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में फसल काटने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी बिहार से तमाम लोग जाते हैं। अपने घर का काम करके जाते हैं। अगर वहां पर कोई इंडस्ट्री होती तो वहां पर भी कोई प्रोडक्शन होता। लेकिन जानबूझ कर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। हम तिवारी जी से स्पेशली कहना चाहेंगे कि वे यू० पी० के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने वहां का दौरा भी किया है और उस इलाके की गरीबी को भी देखा है, वे इस पर विचार करें। वे इसका सर्वे करायें। वहां पर इंडस्ट्रीज जरूर लगाई जानी चाहिएं। यहां कहा जाता है कि यू० पी० में सबसे ज्यादा पोपुलेशन है। वहां पर जो बस्ती जिला है उसकी पोपुलेशन सबसे ज्यादा है। वहां पर रा-मेटिरियल भी बहुत है। फिर भी कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है। ये क्यों नहीं है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या जब तक वे लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे? मैं चहता हूं कि आप वहां का सर्वे करायें और सर्वे के बाद भी जो आप मुनासिब समझें वह इंडस्ट्री वहां पर लगायें। हम नहीं कहते कि जो हम कहते हैं वही आप करें। आप वहां पर इंडस्ट्रीज जरूर लगायें ताकि हजार, डेढ़ हजार युवकों को रोजी रोटी मिल सके। पंजाब को पंजाब बनाने वाला कौन था? वे कैरों साहब थे। यही नजरिया जो कैरों साहब का पंजाब के लिए था वही नजरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित करेंगे तो बाहर के लोग वहां पर काम करने के लिए जायेंगे। चूंकि मैं उस इलाके से आता हूं, इसलिए आपकी नालेज में ये बातें दे रहा हूं।

इन पूर्वी जिलों में हैण्डलूम इंडस्ट्री बहुत ही पोपुलर है। मैं तिवारी जी से कहूंगा कि आप जूट इंडस्ट्री को हैण्डलूम इंडस्ट्री में ले आइये। हमारा बहुत जूट बाहर चला जाता है। अगर आप जूट इंडस्ट्री को हैण्डलूम में कंवर्ट कर देंगे तो लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। जूट के कम्बल बनाये जा सकते हैं। गरीबों को कम्बल मिलते नहीं हैं। वे जूट के टाट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वह गरम होता है। अगर जूट के कम्बल बनाये जायेंगे तो निश्चित रूप से वे सस्ते दाम पर मिलेंगे और जिस चीज को अमीर लोग अपने घरों में बिछाने के लिए उपयोग में लाते हैं उसको गरीब लोग जरूर खरीदेंगे। इसलिए आप जूट को हैण्डलूम इंडस्ट्री में ले आइये। इसमें पचास हजार लोगों को काम मिल सकता है।

इसके बाद मैं आप का ध्यान उन मिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो

[श्री सोहन लाल धूसिया]

सिक हो जाती हैं। आप इंडस्ट्रीज खोलते जाते हैं, लेकिन जब वे सिक हो जाती हैं तो वहां जो 15 सौ मजदूर या हजार मजदूर काम करते हैं उन फैमिलीज का गला घुट जाता है। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर कहते हैं कि वे गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं। लेकिन सिक मिल में लोगों की हालत क्या हो जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब एक अंगुली कट जाती है तो हम उस पर पट्टी बांधते हैं। उसी तरह से इन गरीबों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जब वे भूखों मरते हैं तो चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं और क्राइम्स भी बढ़ने लगते हैं हम यह चाहेंगे कि जितनी सिक इंडस्ट्री है, जो भी सरकार हो वह इस बारे में कन्सलटेंसी एजेंसीज से कन्सल्ट करके उनको इनवाइट करें और उनको रेंट पर दे दिया जाय। इससे न इंडस्ट्री बंद होगी और न लोग भूखे मरेंगे। यदि यह नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री सिक होंगी और बंद होंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यह तिवारी जी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों की तबाही आप लोग कब तक होती देखते रहना चाहेंगे। कोई जरिया ढूंढिये ताकि उनकी तबाही रुक सके। आप उनको इंडस्ट्री नहीं देंगे तो कैसे वहां का विकास होगा। हिमालय की नदियों को आप टेम नहीं कर सकते, उनकी धारा को आप मोड़ नहीं सकते जो कि इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इंडस्ट्री आप देंगे नहीं। तो आखिर वह लोग करें क्या। मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों को जरा आप देख लें। (समय की घंटी)

महोदय, इंडस्ट्री चलती है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज जितनी भी पूर्वी जिलों में हैं वहां आप देख लें कि हर छह महीने के बाद उनकी सर्विसें ब्रेक कर ली जाती है। वे किसी को परमानेन्ट नहीं करेंगे। 6–7 साल तक काम करने वाले कर्मचारी भी टेम्परेरी बने हुए हैं। इनमें जो मिल सिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में तिवारी जी, आपको मालूम है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं और वह एडमिनिस्ट्रेट वह होता है जो सर्विस से रिटायर हो चुका होता है और अगर रिटायर न हो तो सर्विस वाला होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप के पास पब्लिक वरकर्स नहीं हैं, पब्लिक के आदमी नहीं हैं जो आप एक आफिसर को वहां बिठा देते हैं। कल तक जो मिनिस्टर था, एम० पी० रह चुका है, एम० एल० ए० रह चुका है, उसको यह जगह क्यों नहीं देते। अगर एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वह ज्यादा अच्छा काम करेगा। सर्विस वाले को तो आपने लूटने का, खाने का मौका दे दिया। वह जानता है कि मेरा तो कुछ होगा नहीं और जब मौका मिल गया है तो उसका फायदा उठाया जाये। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि यदि किसी भी जगह सिक मिल हो तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वह किसी पब्लिक के आदमी को बनायें। लेकिन हवा कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जो पब्लिक की निगाह में जितना गिरा हुआ होता है उसको उतना ही ऊंचा दर्जा देते हैं, परमोशन देते हैं। ऐसी हालत में क्या किया जाय? (समय की घंटी)

महोदय, दो-एक बात कहकर बैठ जाता हूं। महोदय, क्या आप क्लास फोर और क्लास थ्री वालों के लिये कभी सोचते हैं कि उनके लिये भी मकान की जरूरत है? अगर जरूरत है तो ईंट का भाव इन गरीबों के लिये ऐसा कर दीजिये ताकि वे भी अपने लिये दो कमरे बनवा

सकें। आखिर में रिटायर होकर जायेंगे कहां, रहेंगे कहां। ईंटों का भाव 500 रुपये हजार हो गया है, 70 रुपये से कम में सीमेंट नहीं मिलता है। मुझे यह मालूम नहीं कि यह किस इंडस्ट्री में आता है। लेकिन इन गरीबों के लिये क्लास थ्री और क्लास फोर में जो हैं क्या उनको मकानों की जरूरत पड़ेगी या नहीं यह आप सोचें।

दूसरी चीज, जो 12-14 मील साइकल पर आता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक साइकल की कीमत 450 रुपये, 500 रुपये हो गई है। इसकी कीमत जब पहले यह चली थी 25-30 रुपयें में हम लेते थे। साइकल को आप आटो साइकल कर दें लेकिन इसकी कीमत 1500 से ज्यादा मत कीजिये ताकि 15 मील जो लड़का, जो क्लर्की करता है या क्लास फोर का नौकर है वह किराये के मकान में न जाकर अपने घर से आ जा सके।

आखिर में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी इस बात को मानेंगे कि इनफ्लेशन है। जब गरीब आदमी बाजार में खरीदने के लिये जाता है, आटा, चावल, सब्जी, दाल तो उसे बहुत परेशानी होती है और वह सोचता है कि इतनी तनख्वाह से कैसे गुजारा होगा। जितने भी सरकार के रेट हैं, जिस पर गेहूं खरीदवाते हैं, आप कहते हैं कि इतना मिनिमम है। लेकिन उस किसान को

5 P.M. जो मैक्सीमम प्राइस फिक्स किय गया है उससे ज्यादा कोई व्यापारी नहीं देगा। केवल शब्दों का हेरफेर है इधर से उधर कर दिया है। मैं इतना ही चाहूंगा खास तौर से जो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनको आप कंट्रोल का राशन दिलवा दीजिये। आप जितने में किसान से लेते हैं उतने में ही दिलवा दीजिये तो हम मान जाएंगे कि इनफ्लेशन नहीं है। इसको कौन करेगा? हम सरकार से इतना ही चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज में इन गरीबों का हित अवश्य देख लें।

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में हमारे देश के औद्योगिक विकास और उद्योग मंत्रालय के कार्यकलापों के ऊपर बहस चल रही है। कल का दिन तो ऐसा था जब बहस शुरू हुई तो अधिकांश विपक्ष के ही माननीय सदस्यों ने अपने विचारों का इजहार किया। आज दुर्भाग्य से वे यहां नहीं हैं अपनी मर्जी से इस सदन को छोड़ कर चले गये हैं। मैं चाहता था कि आज कम से कम हम लोग जो कांग्रेस के पक्ष के हैं उनकी बातें भी वे सुनते। श्रीमन्, जो बातें विपक्ष के सदस्य बोले थे उन से मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि वह यह कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में आजादी के 37 साल में किसी किस्म का कोई भी विकास आर्थिक, औद्योगिक हुआ ही नहीं है। मैं जरूरी तो नहीं समझता मगर अब यह कहना आवश्यक हो गया है कि अंग्रेजों के जमाने के औद्योगिक मानचित्र में यदि भारत पर निगाह डाली जाए तो कहीं कहीं बढ़ई की दुकानें और कहीं कहीं लोहार की दुकानें नजर आती थीं और आज के हिन्दुस्तान में, मेरी आवाज उन तक अखबारों के माध्यम से पहुंचेगी सदन में वे नहीं हैं, रेल का इंजिन, मोटर-गाड़ियां बड़ी और छोटी, बिजली की मोटरें, टरबाइंस, एक्सरे की मशीनें, टेलीविज़न-रंगीन और काला, रेडियो दूसरे तमाम उपकरण बड़ी मशीनों को बनाने वाली मशीनें, सभी कुछ हमारे देश में बन रहा है। हर चीज के ऊपर मेड इन इण्डिया की मोहर लगी हुई है। मुझे अफसोस है कि विपक्ष के हमारे दोस्त जानते हुए भी इस बात को तसलीम नहीं करना चाहते। मेरा कुछ ऐसा ख्याल बन गया है वह देख सब रहे हैं मगर उनको चिढ़ एक बात की है कि हिन्दुस्तान के निर्माण, उसको तामीर करने का काम हिन्दुस्तान की

[श्री शान्ति त्यागी]

जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में क्यों डाला। उन्हें इस बात की उदासीनता है कि देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में नये समाज की रचना क्यों हो रही है। इस बात की परेशानी है वरन् जो हमारे देश में विकास हो रहा है उसको वे भलीभांति जानते हैं। एक माननीय सदस्य चौधरी चरण सिंह के द्वारा लिखा हुआ पोथा ले आए और बराबर उसी में से कोट करते रहे। माननीय चौधरी साहब मेरे जिले के हैं और हमारे नेता रहे हैं और मुझे खुद भी जाती तौर पर 40 साल पेशतर उनके साथ राजनीति में काम करने का मौका मिला लेकिन कभी भी राजनीति के इलावा अर्थ नीति की कोई बात, देश के निर्माण की कोई बात, विकास की कोई बात, तामीर की कोई बात चरण सिंह जी ने हम को नहीं बताई। कल तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि देश की इकोनोमी के ऊपर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर वे किताब लिखने लगे हैं। यह पहला मौका है जब उन्होंने इस चीज के ऊपर किताब लिखी है, वरन् देश में बड़ी खेती हो, सामूहिक खेती के वह विरोधी रहे हैं इसके खिलाफ हमेशा असेम्बली में लड़ते रहे, किताबें लिखते रहे हैं। हुक्मदेव नारायण यादव जी यदि यहां पर होते तो मैं उन से पूछता कि उन्होंने नेहरू जी को गांधी जी के खिलाफ खड़ा कर दिया और गांधी जी को नेहरू जी के खिलाफ खड़ा कर दिया। गांधी जी ने कहां लिखा है कि देश में किसी किस्म का कोई बड़ा उद्योग नहीं होना चाहिये, मशीनें नहीं बननी चाहियें? गांधी जी ने किस किताब में कहां लिखा है, पंडित नेहरू ने कहां इस बात की घोषणा की है कि मैं छोटे और लघु, कुटीर उद्योगों का विरोधी हूं और देश में बिल्कुल किसी जगह भी, किसी स्टेट में इन को कायम नहीं करना चाहिए? यह घोषणा पंडित जी ने किस मौके पर, किस स्थान में की है? यह लघु बात है।

इसलिए मैंने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, वह सब उसको देख रहे हैं, मगर चिढ़ इस बात की है कि देश नया जो बन रहा है, समाज नया जो बन रहा है, यह पंडित जी के हाथों क्यों बना और बाद में माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हाथों इस देश की रचना क्यों हो रही है? दुख, तकलीफ और चिंता इस बात की है।

मान्यवर, तिवारी जी के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। यूं तो कई हमारे माननीय सदस्य तो पता नहीं किस लहजे में बात करते हैं—हमारे महाराष्ट्र के सम्मानित सदस्य हैं, बहुत बोलते हैं, विद्वान् भी हैं। माननीय तिवारी जी हमारे देश के नेता हैं और तिवारी जी का सम्पूर्ण जीवन और विचारधारा, कभी भी क्षेत्रवाद से पीड़ित नहीं रही है। हमेशा नेशनलिज्म के दायरे में, सेक्यूलरिज्म के दायरे में, सोशलिज्म के दायरे में उन्होंने सोचा है और चिंतन करना सीखा है, वह फ्रीडम-फाइटर भी हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में वह जन्मे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और दूसरे भाई अगर यह समझते हों कि आज भारत सरकार के उद्योग मंत्री रहते हुए वह सिर्फ उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई छोटी बात, लघु बात कोई सोचने के लिए नहीं हो सकती है।

महाराष्ट्र के हमारे दो साथी जिनका नाम लेना मैं आवश्यक नहीं समझता, सब को मालूम है कि महाराष्ट्र तो बहुत उन्नत स्टेट है—हमें बहुत प्रसन्नता है, वह हमारे देश का हिस्सा है। बम्बई और नागपुर में उद्योग बिठाये गये हैं जो और उन उद्योगों में वहां के लाखों नर-

नारी काम करते हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। वहां के वैज्ञानिक संस्थानों में जो वैज्ञानिक काम करते हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। मगर उत्तर प्रदेश तो हमारे देश का सब से बड़ा हिस्सा है और यह बात बराबर कही जाएगी इशारे से, किसी ढंग से कि तिवारी जी उत्तर प्रदेश के हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश पर उन की बहुत नजरे-इनायत है और उद्योगों के लाइसेंस भी, हर किस्म के, चाहे फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, बिजली हो, शूगर की फैक्टरी हो, सब उत्तर प्रदेश को ही दे रहे हैं। यह बात नहीं है और यह बिल्कुल फैक्ट्स के विपरीत बात है। महाराष्ट्र में जितने लाइसेंस दिये गये हैं, उनका आधा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिले हैं। यह सब लोगों को मालूम है और उत्तर प्रदेश को दुनिया के शासनाध्यक्षों ने आकर के देखा है, दुनिया के डिप्लोमेट्स देखते हैं, हमारे देश के नेता देखते हैं, सब इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जो एक माने में खेतिहर है और उसमें उद्योग बहुत कम हैं और यह पिछड़ी हुई स्टेट है, बैकवर्ड है। तो मैं यह बात आपसे कह रहा था।

अब मैं सिर्फ दो-तीन मिनट आपके लूंगा--आज हमारे कलमाडी साहब ने एक बात और कही कि पब्लिक सेक्टर के उस यूनिट को जो तिवारी जी के अन्तर्गत हो, या और भी कोई यूनिट्स हों, जिनमें बराबर नुकसान हो रहा हो, उसको ज्वाइंट एंटरप्राइज कम्पनी बना देना चाहिए।

मैं कहता हूं कि समाजवाद की दुहाई देने वाले लोग पब्लिक सैक्टर की यूनिट को, जो बीमार हो, जिसमें घाटा हो रहा हो--उसमें अगर यह कहा जाए कि उसका इम्प्रूवमेंट करिए, उसके मेनेजमेंट को बढ़िया कीजिए, इसमें अच्छी टैक्नालोजी लगाइये, यह बात तो समझ में आती है, मगर यह कलमाडी साहब की दलील कि उसको भी व्यक्तिगत हाथों में, चाहे कुछ कम शेयर परसेंट पर ही सही, जिसको सुपुर्द कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि देश में जो समाजवाद के लिए पत्थर है, माइलस्टोन हम बना रहे हैं और जिसको हम कमांडिंग पोजीशन देना चाहते हैं, पब्लिक सैक्टर को, उस को भी अब व्यक्तिगत हाथों में फिर से करवाना चाहते हैं। इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती।

मैं उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके संचालन और मार्गदर्शन में हमारे देश की औद्योगिक पैदावार में इजाफा हुआ है। 1984 की फरवरी में जो हमारी औद्योगिक विकास दर है, वह 11.3 हो गई। हमारे एक भाई अभी यह बोल गये हैं, वह इसका वर्णन कर चुके हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनके मंत्रालय के अधीन हमारे पब्लिक सेक्टर में पिछले वर्ष 2400 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था जो 1983-84 में बढ़ कर अब 276 करोड़ हो गया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं।

जो लोग लघु उद्योग बनाम भारी उद्योग का बेमानी प्रचार इस हाउस में भी कर रहे हैं और बाहर अखबारात में भी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय तिवारी जी की इस कामयाबी को देखें कि 1982-83 के वर्ष में लघु और छोटे उद्योगों में 35 हजार करोड़ का उत्पादन हुआ जब कि 1981-82 में 32,600 का। मैं विपक्ष से कह रहा हूं कि भारत के करीब 80 लाख नर-नारी उद्योगों में काम करते हैं। यह कहना कि बड़े उद्योग लगा कर बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है भ्रामक प्रचार है। देश के भाइयों को यह समझना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो

[श्री शांति त्यागी]

मेरठ जनपद है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है । उसकी तरफ मैं माननीय तिवारी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अध्यक्ष जी, अभी तिवारी जी मेरठ तशरीफ ले गये थे । उन्हें मेरठ से मुहब्बत है । उन्हें सब स्टेटों से मुहब्बत है, लेकिन हम जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वह सौभाग्य से हमारे प्रदेश में पैदा हुए हैं, उन पर हमारा विशेष हक है तो हमारी आकांक्षा होने में कोई बुराई की बात नहीं है , हालांकि हम जानते हैं कि आकांक्षा को वह पूरा करते नहीं हैं । मैं मेरठ के नागरिक की हैसियत से उन से—इसलिए नहीं कि वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं—प्रार्थना करूंगा कि मेरठ में और समूचे उत्तर प्रदेश में जहां-जहां मुनासिब समझते हों, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां की क्लाइमेट को रास आने वाले जो उद्योग लगवाये जा सकते हों वह लगवाने की कृपा करें । इन अल्फाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का टाइम दिया । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में और उन के हाथों देश का उद्योग एक नये ढंग से पनप रहा है और रफ्ता-रफ्ता उद्योग देहातों तक पहुंच रहा है और देश के करोड़ों नवयुवक उनमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं । आप बहुत बधाई के पात्र हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now, Shri Janardhna Poojary will lay papers on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE (Contd.)

Notification of the Ministry of Finance 'Department of Revenue) Issued under the Centra] Excise Rules, 1944 and related papers

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY . OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Central Excise Rules, 1944:—

(i) Notification No. 107|84-CE pub-(in the Gazette of India dated fee 9th May, 1984, together with an natory memorandum regarding effective rate of basic excise duty on EC grade ingots, Ec billets, EC grade wire bars and EC grade wire rods.

(ii) Notification No. 108/84-CE published in the Gazette of India dated the 9th May, 1984, together with an explanatory memorandum seeking to reduce the effective rat:; of basic excise duty on aluminium.

(Hi) Notification No. 10 published in the Gazette of India dated 9th May, 1984, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 270/82-CE dated the 13th November, 1982.

[Placed in Library. See No. LT-784 for (i) to (iii)]

Hfications of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under section 159 of the Customs Act 1962 and related papers

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:

(i) Notification No. 123|84-Cus-toms published in Gazette of India dated the 9th May, 1984, together with an explanatory memorandum prescribing the new ratea of additional duty of customs (Countervailing duty of . customs) on the aluminium' and its products.

(ii) Notification No. 124[84-Cus-toms published in Gazette of India dated the 9th May, 1984, together with an explanatory memorandum rescinding Notification Nos. 94-Cus-